

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15

लखनऊ:दिनांक 18 अगस्त 2020

विषय:- " महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन " की स्थापना विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- डीजी-सात-एस-3(80) / 2019 दिनांक- 11.12.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों का उत्पीड़न रोकने, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने और उनको सहायता प्रदान करने तथा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु प्रदेश में एक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त संगठन में पुलिस विभाग के अन्तर्गत कार्यरत महिला उत्पीड़न सम्बन्धी सभी इकाइयों जैसे- महिला सम्मान प्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ, 1090 महिलाओं से सम्बन्धित लोक शिकायत में प्राप्त होने वाली शिकायतों को एक ही अधिकारी के नियंत्रण में बनाये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत तथा उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु "अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास सुरक्षा " के पद एवं कार्यालय के गठन की संरचना का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि सीबीसीआईडी के अन्तर्गत " पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ " हेतु सृजित पदों को तथा वूमन पावर लाइन -1090 हेतु निर्धारित पदों को महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित पदों में समाहित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

1. शासनादेश स0- 9236/आठ-1-150 (16) /88 दिनांक-27.02.1989 स0- 8528/छ:-1-150 (16) / 88 दिनांक-04.12.1989 द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन स्थापित पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2. शासनादेश स0- 452/छ -पु0-15-2014 दिनांक 05.09.2014 द्वारा पुलिस महानिदेशक के अधीन एक महिला सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया गया एवं विस्तृत दिशा- निर्देश जारी किये गये। शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को इस प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में नामित करने के निर्देश दिये गये तथा प्रकोष्ठ में आवश्यक अन्य कार्मिकों की तैनाती पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध जनशक्ति से किये जाने के निर्देश दिये गये। महिला सम्मान प्रकोष्ठ के कर्तव्य एवं उद्देश्य सीबीसीआईडी में सेक्टर स्तर पर स्थापित पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ के विवेचनाओं का प्रशासनिक पर्यवेक्षण व अनुश्रवण।

3. गृह सचिव, भारत सरकार के अ०शा०प०स०- 15020/08/2007- एटीसी दिनांक 16.06.2010 के क्रम में प्रदेश में समस्त एण्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTUs) का पर्यवेक्षण महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में यह प्रदेश की नोडल एजेन्सी होगी।

4. महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में वूमेन पावर लाइन- 1090 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय / अनुभवण / पर्यवेक्षण का कार्य।

- वूमेन पावर लाइन नव गठित महिला सम्मान प्रकोष्ठ के अधीन एवं निर्देशन में कार्य करेगी। वूमेन पावर इन हेतु आवश्यक कार्मिकों की तैनाती एवं संसाधनों की पूर्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा उपलब्ध संसाधनों से की जायेगी।

- वूमेन पावर लाइन-1090 का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा। इसका नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित रहेगा। इसी नियंत्रण कक्ष से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से दूरभाष स०- 1090 पर काल प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

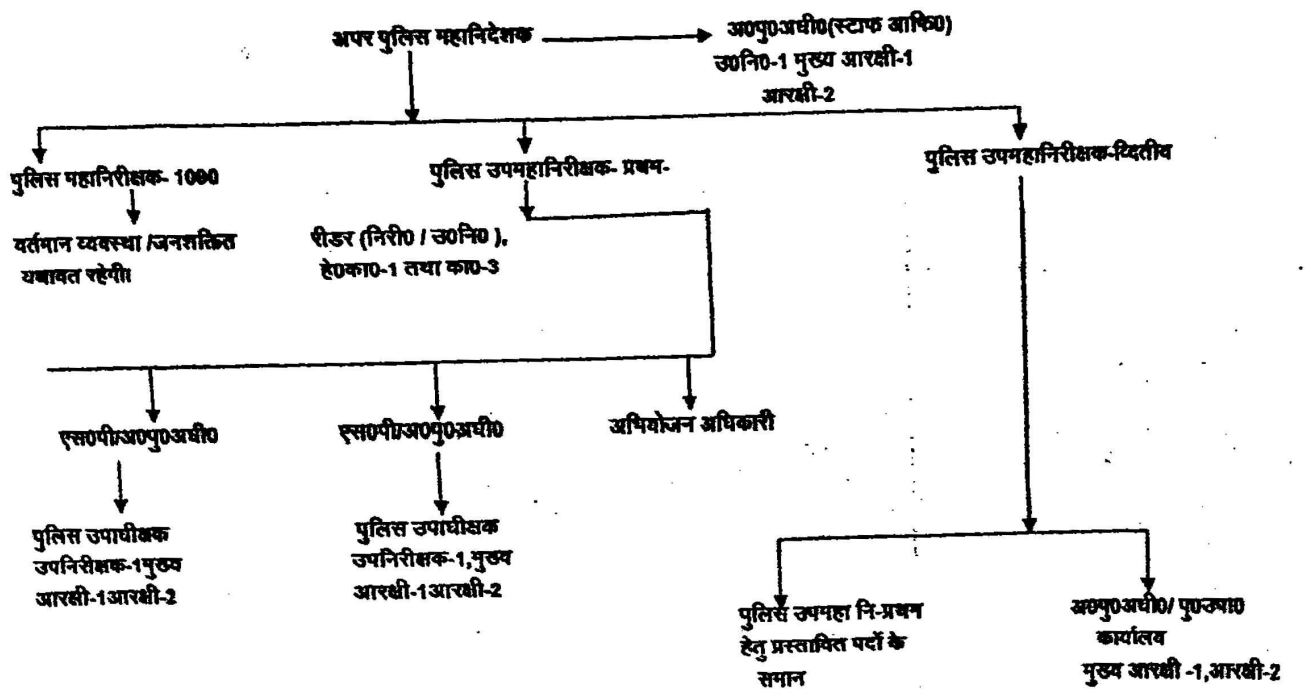
5. शासनादेश स०-586/छ:-पु-15-2014 दिनांक 29.09.2014 द्वारा वूमेन पावर लाइन- 1090 सेल का सभी कार्य अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र० के पर्यवेक्षण में किया गया है।

3. उपर्युक्त प्रस्तर -1 के क्रम उल्लेखनीय है कि अपर पुलिस महानिदेशक, "महिला एवं बाल विकास सुरक्षा संगठन" की व्यवस्था हेतु किसी भी नवीन पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत होगा:-

संरचनात्मक ढाँचा

"महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन" अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के सामान्य दिशा- निर्देश में कार्य करेगा।

संरचना



कार्य एवं उत्तरदायित्व

मुख्यालय एवं जोन स्तर पर कार्यरत महिला एवं बाल सुरक्षा के कार्य इस प्रकार होंगे-

1. महिलाओं के उत्पीड़न के संबन्ध में जनपदीय पुलिस की कार्यवाही का अनुश्रवण, आकलन तथा मार्गदर्शन के अतिरिक्त महिलाओं संबन्धी अपराधों के मात्रासिक आंकड़ों का संकलन करना।
2. प्रताड़ित महिलाओं को तत्परता से उचित सहायता उपलब्ध कराना।
3. जेण्डर सेन्सिटाइजेशन हेतु सेमीनार, ट्रेनिंग वर्कशाप आदि का प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से आयोजन किया जाना।
4. महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के सम्बन्ध में पुलिसजनों के लिए पीटीसी, पीटीएस, आरटीसी, आदि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना।
5. जनपदीय पुलिस थानों को थाना सत्र पर महिलाओं की सुरक्षा इत्यादि सम्बन्धी अद्यतन विधिक जानकारी से शिक्षित करना।
6. महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु सामाजिक चेतना विकसित करना।
7. महिलाओं के अधिकारों का व्यापक प्रचार प्रसार करना।
8. महिलाओं के उत्पीड़न की समस्या के मूल में जाकर उसके समाधान के सम्बन्ध में शोध करना।
9. मुख्यालय एवं जोन स्तर पर इन संगठनों में नियुक्त अधिकारियों द्वारा आकस्मिक फील्ड विजिट कर समीक्षा किया जाना।
10. ह्यूमेन ट्रेफिकिंग के विरुद्ध कार्ययोजना बनाना एवं इसे रोकने हेतु की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण एवं आकलन करना।
11. गृह सचिव, भारत सरकार के अशा० प० स०- 15020/08 /2007 - एटीसी दिनांकित 16.06.2010 के क्रम में प्रदेश में स्थापित समस्त एण्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग व पर्यवेक्षण इस नवगठित प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में यह प्रदेश की नोडल एजेंसी होगी।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, एवं निदेशक, फारेन्सिक लैब के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों का डेटाबेस उदाहरण के लिए डीएन. डाटा बैंक फार मिसिंग पीपुल का सृजन- अनुरक्षण एवं यथा आवश्यक अन्य राज्यों की पुलिस तथा उ०प्र० पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना। साथ ही फारेन्सिक सुविधा एवं सहायता का अनुश्रवण एवं त्वरित उपलब्धता कराना।
13. महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में वूमन पावर लाइन, 1090 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वय/ अनुश्रवण / पर्यवेक्षण का कार्य।
14. आईजीआरएस /1090/ सीएम हेल्पलाइन इत्यादि से प्राप्त महिला उत्पीड़न संबन्धी शिकायतों को अभिलिखित करते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
15. अन्य विभागों तथा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि विभागों द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कराना। अन्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्सीय, न्यायिक, मनोवैज्ञानिक, परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी पुलिस विभाग की ओर से समन्वय व सहयोग सुनिश्चित कराना।
16. मुख्यालय स्तर पर इस इकाई में नियुक्त अधिकारियों द्वारा आकस्मिक फील्ड विजिट कर समीक्षा किया जायेगा।
17. शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य एवं दायित्व का निर्वहन।
18. अभिनव प्रयोगों आई०टी० का सदुपयोग करते हुए बेसाइट, मोबाइल, एप्स, जियोफेसिंग, आदि तकनीकी का सृजन कर इसका उपयोग पुलिस महानिदेशक उ०प्र० सुनिश्चित करेंगे।
19. महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यकारी आदेश पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा निर्गत किया जायेगा।

उपरोक्त संगठनात्मक व्यवस्था हेतु किसी भी नवीन पद सृजन नहीं किया जायेगा । सीबीसीआईडी के अन्तर्गत पुलिस महिला सहायता प्रकोष्ठ " हेतु सृजित पदों को अपर पुलिस महानिदेशक , महिला एवं बाल सुरक्षा के अन्तर्गत समायोजित कर तथा वूमन पावर लाइन -1090 हेतु निर्धारित पद महिला एवं बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित पदों समाहित किया जायेगा ।

4. कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या 730 /6-मू0-15/2020-6(15)/2018 एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 शासन ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ / 1090 उ0प्र0 लखनऊ ।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप0पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 ।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र ।

आज्ञा से
(राम निवास शर्मा)
विशेष सचिव